सं. 1(2)/2025-समन्वय

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

****

अप्रैल, 2025 माह के लिए डीपीई का मासिक सारांश

1. सीपीएसई और अन्य सरकारी संगठनों में पूंजीगत व्यय:

वर्ष 2025-26 के लिए चुनिंदा सीपीएसई और अन्य सरकारी संगठनों जिनका पूंजीगत व्यय लक्ष्य 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक है, के लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्य 7.85 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।

2. सीपीएसई का संचालन:

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने 2017, 2007, 1997, 1992 और 1987 के औद्योगिक महंगाई भत्ता वेतनमानों का अनुसरण करने वाले सीपीएसई के लिए महंगाई भत्ता (डीए) दरों में 01.04.2025 से संशोधन किया और 7वें सीपीसी, 6ठे सीपीसी और 5वें सीपीसी सीडीए वेतनमानों का अनुसरण करने वाले सीपीएसई के लिए महंगाई भत्ता दरों में भी संशोधन किया।

3. अंतर-मंत्रालयी बैठकें और आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए)/मंत्रिमंडल नोट:

(i) अप्रैल, 2025 माह के दौरान सीएमसीडी की 01 बैठक आयोजित की गई।

(ii) डीपीई ने 8 अप्रैल, 2025 को 31 रत्न सीपीएसई के साथ उनकी उत्तराधिकार आयोजना और नेतृत्व विकास योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक का आयोजन किया।

(iii) डीपीई ने मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और भोपाल में अप्रैल, 2025 माह के दौरान 'सीपीएसई-स्पैरो प्रणाली के अभिगम के लिए संबंधित सीपीएसई अधिकारियों के लिए वीपीएन खाते बनाने की प्रक्रिया पर' एक कार्यशाला आयोजित की।

4. सीपीएसई को बंद करने का प्रस्ताव:-

नई पीएसई नीति दिनांक 04.02.2021 के अनुसरण में, वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 7 सीपीएसई (ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीआईसी) और नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीसी) के साथ इसकी 5 सहायक कंपनियों) और वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 2 सीपीएसई (स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी) और प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीईसी)) को बंद करने के संबंध में सीसीईए नोट के मसौदे की अग्रिम प्रति दिनांक 23.08.2022 को प्रधान मंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजी गई थी। इसके अतिरिक्त, जब कभी प्रधानमंत्री कार्यालय ने पूछा तो सूचना/स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किए गए। डीपीई ने हाल ही में अपनी अंतर्विभागीय टिप्पणी दिनांक 09.09.2024 और 04.11.2024 के माध्यम से क्रमशः वस्त्र मंत्रालय और वाणिज्य विभाग के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की। तब से, मामला प्रधानमंत्री कार्यालय के पास लंबित है।

5. क्षमता निर्माण:

डीपीई के 85 कर्मचारियों (वाईपी/वाईए सहित) ने 30 अप्रैल, 2025 तक आई-जीओटी पोर्टल पर 2864 पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं।

6. मिशन भर्ती:-

26 अप्रैल, 2025 को आयोजित रोजगार मेले के 15वें चरण में सीपीएसई के 3144 नव नियुक्तों को शामिल किया गया।

7. एएमआरसीडी मामलों की स्थिति: -

दिनांक 05.05.2025 तक एएमआरसीडी डैशबोर्ड से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर, पोर्टल पर 204 मामले रिपोर्ट किए गए। वित्तीय सलाहकारों के स्तर पर 51 मामलों को खारिज कर दिया गया। 51 मामलों का निपटारा कर दिया गया है और 73 मामले निर्णय के लिए सचिवों की समिति के पास हैं। शेष 29 मामले संबंधित वित्तीय सलाहकारों के पास उनकी जांच और अनुमोदन के लिए लंबित हैं। ब्यौरा **अनुलग्नक क, ख, ग** में दिया गया है।

*****